



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863]  
No. 863]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2009/ज्येष्ठ 7, 1931  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2009/JYAISTHA 7, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2009

का.आ. 1372(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में, माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा शर्मा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिन्हें मेघालय के हनीवट्टेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (एच एन एल सी) नामक संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत एक संदर्भ भेजा गया था, की अध्यक्षता में गठित न्यायाधिकरण के आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा शर्मा की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण के समक्ष के मामले में : मेघालय के हनीवट्टेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने से संबंधित अधिसूचना सं. का.आ. 2665(अ) दिनांक 16-11-2008, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भाग II, खण्ड (ii)।

आदेश

भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16 नवम्बर, 2008 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2665(अ) के द्वारा, केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के

अन्तर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय के हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कौंसिल (जिसे इसमें इसके बाद 'एच एन एल सी' कहा गया है) को इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठन सहित तत्काल प्रभाव से इस आधार पर विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया है कि उक्त संगठन तथा इसके विभिन्न गुटों का घोषित उद्देश्य हिंसात्मक तरीकों से मेघालय राज्य में खासी और जैन्तिया जनजातियों की व्यापक आबादी वाले क्षेत्रों को भारत से अलग करना है।

अधिसूचना में यह कहा गया है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एच एन एल सी अपने संगठन के लिए निधियां जुटाने हेतु आम जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन-वसूली और लूट-खसोट के कृत्यों में संकलप्त रहा है; जबरन धन बसूलने और डराने-धमकाने के कृत्यों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही गुटों के साथ सम्बन्ध बनाए हुए है तथा अपने काइरों के आश्रय-स्थल और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ कुछ पड़ोसी देशों में स्थिर चला रहा है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि एच एन एल सी वर्ष 2006 और वर्ष 2007 प्रत्येक में हिंसा की तीन-तीन घटनाओं और वर्ष 2008 में (30 जून, 2008 तक) एक घटना में संलिप्त था जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः वर्ष 2006 और 2007 में एक सुरक्षा कर्मी सहित एक और दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार की यह राय है कि, "एच एन एल सी की पूर्वोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यदि इन्हें तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया तो एच एन एल सी अपने को फिर से संगठित और हथियारों से लैस कर लेगा, अपने काइरों को बढ़ाएगा, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करेगा, नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की हत्याएं करेगा तथा अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तेज करेगा।"

चूंकि इस अधिनियम के अनुसार, एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण को एक संदर्भ भेजा जाना अपेक्षित है, अतः भारत सरकार ने एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के प्रयोजनार्थ इस न्यायाधिकरण का गठन करके इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 को एक अधिसूचना जारी की है जिसका पाठ निम्नानुसार है :-

“गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2008

का. आ. 2860 (अ) - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मेघालय के हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कौंसिल (एच एन एल सी) को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के प्रयोजनार्थ, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा शर्मा की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/53/2008-एन ई-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव”

11 दिसम्बर, 2008 की उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना के साथ एच एन एल सी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का सार इस न्यायाधिकरण के अवलोकन एवं सूचना हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो इस प्रकार है :-

#### “एच.एन.एल.सी. के लक्ष्य और उद्देश्य:

एचएनएलसी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका उद्देश्य हन्नीवट्रेप लोगों (खासी और जैंतिया जनजातियों) को भारत सरकार के अधिकारवादी शासन से मुक्त करना, खासी लोगों और मेघालय की अन्य जनजातियों को शोषण से बचाना, स्थानीय संस्कृति को बचाए रखना और सामाजिक बुराइयों को मिटाना था। यह संगठन खासी समाज को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

#### हिंसा की स्थिति

इस गुट द्वारा की गई हिंसा में काफी कमी आई है। वर्ष, 2006, 2007 और 2008 (30.06.2008 तक) के दौरान, एचएनएलसी क्रमशः तीन, तीन और एक हिंसक घटनाओं में शामिल था। एचएनएलसी की इन हिंसक

घटनाओं के फलस्वरूप वर्ष, 2006 और 2007 में क्रमशः एक व्यक्ति और दो व्यक्तियों (एक सुरक्षा बल कर्मी सहित) की मौत हो गई। तथापि इस गुट ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से आह्वान किया है तथा राष्ट्रीय दिवसों के प्रति विरोध स्वरूप इन दिनों में बंद का अनुपालन करने हेतु लोगों से अपील करता है। एचएनएलसी राज्य में यूरेनियम के खनन का भी विरोध करता रहा है। 10 जनवरी, 2008 को, इस गुट ने धमकी दी कि वह मेघालय में यूरेनियम के खनन का समर्थन करने वाले किसी संगठन अथवा व्यक्ति को माफ नहीं करेगा क्योंकि यह धातु हिन्नीवट्रेप लोगों (खासी और जैतियां जनजातियाँ) की अधिकारपूर्ण सम्पत्ति है न कि भारत की।

एचएनएलसी के स्वयं-भू अध्यक्ष जुलियास डोरफांग जिसने 23 जुलाई, 2007 को आत्मसमर्पण किया था, से की गई पूछताछ से पता चला है कि शिलांग क्षेत्र से जबरन धन वसूली इस गुट के लिए निधियों का मुख्य स्रोत रहा है।

#### पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूमिगत गुटों के साथ संबंध

इस गुट के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (विश्वमोहन डेबबारम्मा) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (ईसाक-मुईबाह) [एनएससीएन (आई/एम)] के साथ संबंध कायम हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में इस गुट के शिविर अथवा शरण-स्थली हैं और इसके शीर्ष नेता, बोबी मारविन, जो स्वयं-भू कमांडर-इन-चीफ हैं, तथा चेरीस्टरफील्ड थांगरव्यू, जो तथाकथित महासचिव हैं, बंगलादेश से अपनी गतिविधियों को चलाते हैं।

#### इस गुट के प्रभाव वाले क्षेत्र, काइरों की संख्या तथा हथियार

एचएनएलसी मुख्यतः मेघालय की खासी पहाड़ियों में सक्रिय है। एचएनएलसी के काइरों की संख्या 50 अथवा 60 होने का अनुमान है। इस समय इस गुट के पास कुल हथियार 20 होने का अनुमान है जिनमें ए के श्रृंखला

वाली रायफल्स, लाइट मशीन गर्ने एवं रायफर्ले शामिल हैं।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, एचएनएलसी को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 15 नवम्बर, 2008 से आगे ओर दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित आधारों पर विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था:

- (i) मेघालय राज्य जहां बड़ी संख्या में भारत से खासी और जैतिया जनजातियां बसी हुई हैं, को भारत से पृथक् करने के एचएनएलसी के उद्देश्य की खुले तौर पर घोषणा की गई है;
- (ii) एचएनएलसी द्वारा अपने संगठन के लिए निधियां एकत्र करने के लिए नागरिकों को डराना और लूट खसोट करना जारी है;
- (iii) यह लूट खसोट तथा डराने धमकाने की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है;
- (iv) यह शरणस्थलों तथा अपने काइरों के प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ बंगलादेश में लगातार शिविरों को बनाए हुए है।

11 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना के अनुसरण में इस न्यायाधिकरण ने अपनी 09 जनवरी, 2009 की पहली बैठक में निदेश दिया था कि एच एन एल सी को अधिनियम की धारा 4 (2) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा जाए कि वे ऐसी नोटिसों के संवितरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि क्यों न उसे एक विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए और क्यों न 16 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना में की गई घोषणा को पुष्ट करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया जाए। यह भी निदेश दिया गया था कि उपरोक्त संगठन को दी जाने वाली इन नोटिसों को, दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में तथा इलाके के ऐसे दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके शामिल किया जाए जहां इस संगठन के कार्यालय हों अथवा जहां मेघालय राज्य में और इसके बाहर उनकी उपस्थिति पाई जाती हो तथा उसकी एक प्रति उक्त संगठन के कार्यालय के सुविज्ञ हिस्सों, यदि कोई हों, पर भी चिपकायी जाए तथा पंजीकृत डाक से अथवा अन्यथा उक्त

संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के पत्रों, यदि कोई हों, पर भी तामील की जाए। यह भी निदेश दिया गया था कि उन क्षेत्रों में, जहां पर उक्त एसोसिएशन की गतिविधियां आमतौर पर चलाई जा रही हों, वहां नोटिसों की विषय-वस्तु एवं न्यायाधिकरण के मकान की अधिसूचना के बारे में ध्वनि विस्तारकों के साथ-साथ ढोल पीटकर मुनादी कराई जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी निदेश दिया गया था कि नोटिसों को जिला अथवा तहसील मुख्यालयों पर प्रत्येक जिलाधीश/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा उपायुक्त के कार्यालय एवं बाजार स्थलों पर चिपकाया जाए। अन्त में, केन्द्र सरकार को यह भी निदेश दिया गया था कि वह इलेक्ट्रानिक मीडिया अर्थात् प्रसारण/दूरदर्शन के द्वारा भी इसका प्रसार सुनिश्चित करे।

इस प्रकार पारित आदेशों के फलस्वरूप गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री आर. आर. झा द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2009 का एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था कि उक्त संगठन को दिनांक 09 जनवरी, 2009 के आदेश में यथा निर्देशित नोटिसें भिन्न-भिन्न तरीकों से तामील कर दी गई थी। इस न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार ने भी, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से नोटिसों को तामील करने एवं प्रकाशित करने के बारे में उठाए गए कदमों का सत्यापन करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। डॉ. श्री रंजन, आयुक्त एवं सचिव, राजनीतिक विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग द्वारा भी दि. 21 फरवरी, 2009 को एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया था। उक्त डॉ. श्री रंजन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि दि. 9 जनवरी, 2009 के न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा यथा निर्देशित नोटिसों को उसमें बताए गए तरीकों से जारी कर दिया गया था। उन्होंने, नोटिसों के प्रकाशन को दर्शाती समाचार पत्रों की कतरनों की प्रतियां तथा इस तथ्य के प्रमाण भी रिकार्ड में प्रस्तुत किए कि नोटिसों को आकाशवाणी के शिलांग केन्द्र द्वारा प्रसारित किया गया था एवं दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग द्वारा टेलीकास्ट किया गया था।

नोटिसों के तामील किए जाने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति एच एन एल सी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं आया और न ही उक्त संगठन की ओर से न्यायाधिकरण अथवा इसके रजिस्ट्रार के समक्ष कोई याचिका, संदेश, जवाब अथवा पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः इस प्रकरण को एक-तरफा

साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निर्धारित किया गया जिन्हें 26 मार्च, 2009 तथा 27 मार्च, 2009 को शिलांग में और फिर 20 अप्रैल, 2009 को दिल्ली में रिकार्ड किया गया।

केन्द्रीय सरकार ने अपने मामले के समर्थन में गृह मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक, श्री आर. आर. झा से पूछताछ की। उन्होंने दिनांक 26 फरवरी, 2009 को एक शपथ-पत्र भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जिसे एस डब्ल्यू- 9/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने बयान दिया कि एच एन एल सी की गतिविधियों से जुड़े तथ्य, उनके शपथ-पत्र में समाविष्ट हैं तथा उक्त को उनके प्रमाण के हिस्से के रूप में पढ़ा जाए। श्री आर. आर. झा के शपथ-पत्र के अनुसार, एच एन एल सी का गठन 1992 में हुआ था। इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों में, हन्नीवट्रेप लोगों (खासी एवं जैन्तिया जनजातियों) को भारत सरकार के कथित अधिकारवादी शासन से मुक्ति दिलाना शामिल है। इस संगठन का उद्देश्य मेघालय राज्य के उन क्षेत्रों को भारत से अलग करना है, जो खासी एवं जैन्तिया बहुल हैं। शपथ-पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि एच एन एल सी खासी समाज के विभाजन के किसी भी प्रयास के विरुद्ध संघर्ष करने की कसम खाता है तथा यह नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस तथा स्वाधीनता दिवस के बहिष्कार के लिए आह्वान करता है और राष्ट्रीय अवकाशों के प्रतिरोध-स्वरूप लोगों से इन दिनों में बंद आयोजित करने की अपील करता है। शपथ-पत्र में यह भी कहा गया है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, एच एन एल सी अपने संगठन के लिए धन की उगाही हेतु लगातार नागरिकों को भयभीत करता है और लूट-खसोट करता है और यह तथ्य एच एन एल सी के स्वयं-भू अध्यक्ष जूलियस डॉरफेंग, जिसने 23 जुलाई, 2007 को आत्म समर्पण कर दिया था, से पूछताछ से भी उजागर हुआ था, जिसने यह भी उद्घाटित किया था कि शिलांग क्षेत्र से की गई लूट-खसोट संगठन के लिए निधियों का एक मुख्य स्रोत रहा है। शपथ-पत्र में यह भी कहा गया है कि एच एन एल सी ने राज्य में यूरेनियम के खनन का विरोध किया है और इसने 10 जनवरी, 2008 को धमकी दी थी कि मेघालय में यूरेनियम-खनन का समर्थन करने वाले किसी भी संगठन अथवा व्यक्ति को बखशा नहीं जाएगा क्योंकि उक्त खनिज-सम्पदा पर हन्नीवट्रेप लोगों (खासी एवं जैन्तिया जनजातियों) का अधिकार है न कि भारत का। शपथ-पत्र के अनुसार, इस संगठन के प्रतिबंधित संगठन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.); दूसरे प्रतिबंधित संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (बिश्वमोहन देबबर्मा) तथा नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड



(इसाक-मुइवाह), {एन.एस.सी.एन. (आई./एम.)} के साथ लगातार संबंध बने हुए हैं। इसके बांग्लादेश में कैंप अथवा आश्रय-स्थल हैं और इसके शीर्षस्थ नेता बॉबी मरविन, जो स्वयं-भू कमांडर-इन-चीफ हैं एवं चेरिस्टर फील्ड थांगक्यू, जो स्वयं-भू महासचिव हैं, लगातार बांग्लादेश से गतिविधियां चलाते हैं। इस संगठन के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विधि-विरुद्ध संगठनों से संबंध बनाए हुए है। बयानकर्ता श्री आर. आर. झा ने अपने शपथ-पत्र के साथ-साथ वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 के दौरान एच.एन.एल.सी. द्वारा की गई हिंसक वारदातों के ब्यौरे का अभिलेख भी प्रस्तुत किया तथा इसे एक्स. एस. डब्ल्यू-9/2 के रूप में प्रमाणित किया। एक्स. एस. डब्ल्यू -9/2 के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2007 को पुलिस ने क्लीव कालोनी में एक वाहन को रोका जिसमें तीन एच एन एल सी विद्रोही यात्रा कर रहे थे, और इस कारण एक मुठभेड़ हुई जिसमें तीन विद्रोही एवं उनके दो समर्थक मारे गए तथा दो पुलिस कार्मिकों को भी चोटें आई, (थाना-लैतुमखराह-शिलांग, पूर्वी खासी पर्वतीय जिला)। पुनः 07 नवम्बर, 2007 को पुलिस और एच एन एल सी विद्रोहियों के बीच पहामुमदोह में एक मुठभेड़ हुई जिसके परिणामस्वरूप एक विद्रोही मारा गया और पुलिस उपाधीक्षक (आर. पी. डिंग्दोह) को गंभीर चोटें आयीं। इस घटना में, दो विद्रोही पकड़े गए तथा शेष दो भागने में सफल रहे। बाद में, घायल पुलिस उपाधीक्षक ने चोटों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया (थाना-नांगपोह, री-भोई जिला)। 16 दिसम्बर, 2007 को पुलिस ने पुनः नारपुह रिजर्व फोरेस्ट से एचएनएलसी के दो भूमिगत उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने जंगल में उनके छिपने के अड्डों पर छापा मारा जिससे भूमिगत उग्रवादियों (एचएनएलसी-4, एनएलएफटी/बी-3) के साथ मुठभेड़ हुई। तथापि, किसी भी पक्ष से किसी के मारे जाने/घायल होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा भूमिगत उग्रवादी बचकर भाग निकले (पुलिस थाना-खेलरीहाट जैतिया हिल्स जिला)। अंत में 26 मार्च, 2008 को आसूचना ब्यूरो, मेघालय से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने एचएनएलसी के एक माइयूल को विफल कर दिया। मुठभेड़ में दो भूमिगत उग्रवादी मारे गए तथा छः को गिरफ्तार कर लिया गया (पुलिस थाना उमकुंग, जैतिया हिल्स जिला)।

जहां तक जबरन धन वसूली की घटना का संबंध है, प्रदर्श एस डब्ल्यू-9/2 से यह पता चलता है कि 15 जनवरी, 2008 को एचएनएलसी ने मैसर्स हिल्स सीमेंट फैक्ट्री, मिन्के (जैतिया हिल्स जिला) को 1 करोड़ रुपये की मांग का एक नोट सौंपा था तथा भुगतान न किए जाने की



स्थिति में गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। 20 मई, 2008 को भी मेघालय पुलिस ने एक एचएनएलसी कॉडर (बी-नांगलेट-23 वर्ष) को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह नांगजिरी गांव (पश्चिमी खासी हिल्स जिला) में कोयला निर्यातकों से जबरन धन वसूली का प्रयास कर रहा था। तथापि अन्य दो कॉडर बचकर भाग निकलने में सफल रहे।

जहां तक मेघालय राज्य का संबंध है, उसने अपने आयुक्त एवं सचिव, राजनैतिक विभाग, मेघालय सरकार, अर्थात् डा. श्रीरंजन से पूछताछ की जिन्होंने साक्ष्य में अपना 21 फरवरी, 2009 का शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा उसे प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/1 के रूप में सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि एचएनएलसी मेघालय के चार जिलों अर्थात् पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, जैतिया हिल्स तथा रि-भोई में बहुत सक्रिय है। उन्होंने यह भी बताया कि एचएनएलसी के लक्ष्य और उद्देश्य का उल्लेख उनके शपथपत्र में विस्तार से किया गया है। उनके अनुसार, एचएनएलसी सशस्त्र संघर्ष के द्वारा अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास कर रही है तथा एनसीसीएन, एमडीएफबी और एनएलएफटी के साथ मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एचएनएलसी पर पूर्व में लगाया गया प्रतिबंध इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा इसके सदस्यों को गिरफ्तार कराने में सहायक रहा है तथा उन्होंने यह अनुरोध किया कि इस तथ्य के मद्देनजर, कि ये अभी भी इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, इस पर लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखा जाए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने शपथपत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/1, जो उन्होंने साक्ष्य में प्रस्तुत किया था, के अनुसार एचएनएलसी निधियां इकट्ठी करने के लिए जबरन धन वसूली तथा आम जनता, व्यवसायों आदि को लूटने में संलिप्त है। यह अनेक घरानों तथा व्यावसायिक स्थापनाओं से जबरन धन वसूली करने के लिए महिलाओं की सेवाएं भी किराए पर ले रही है। इसके समर्थन में उक्त आशय की खबरों वाली अखबारों की कतरन प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/9 के रूप में रिकॉर्ड में लगाई गई हैं। इस शपथपत्र में आगे यह उल्लेख किया गया है कि शस्त्र जुटाने तथा धन वसूली अभियान को जारी रखने के लिए एचएनएलसी पूर्वोत्तर में लगभग सभी उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध बनाए हुए है तथा जैतिया हिल्स में एनएलएफटी, पश्चिमी खासी हिल्स में एनएससीएन (आई-एम) तथा रि-भोई जिले में एनडीएफबी जैसे उग्रवादी संगठनों से मदद ले रही है। यहां पुनः इस प्रकार की सूचना वाली अखबार की कतरन प्रस्तुत की गई है तथा प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/10 के रूप में रिकॉर्ड में सिद्ध की गई है। इस शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एचएनएलसी के शीर्ष कॉडर बंगलादेश में छिपे हुए हैं जहां से वे अपनी अवैध, नापाक तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि एचएनएलसी ने बाइनीहाट से उद्योगपतियों का फिरोती के लिए अपहरण करने की योजना बनाई तथा यह रि-भोई जिले के पाहम उम्डोह जंगल में शिविर लगा रही है। तथापि, पुलिस उपाधीक्षक, रेमण्ड डींगडों के नेतृत्व में पुलिस दल के द्वारा इस संगठन के छिपने के अड्डे पर धावा बोलने से उक्त योजना विफल हो गई। इसके बाद चली मुठभेड़ में पुलिस उपाधीक्षक गम्भीर रूप से घायल हो गए तथा आर्मी हास्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक उग्रवादी भी मारा गया तथा दो उग्रवादियों को मुठभेड़ स्थल से गिरफ्तार किया गया। इस घटना का एक अखबार की कतरन प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/11 में जिक्र किया गया है। शपथपत्र में यह भी

उल्लेख किया गया है कि एचएनएलसी ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), द नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी) तथा नेशनल फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) जैसे अन्य राष्ट्र विरोधी विद्रोही संगठनों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर लिए हैं जिससे यह पक्का विश्वास हो गया है कि निकट भविष्य में एचएनएलसी और अधिक संकट खड़ा करेगी और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रभुसत्ता को गम्भीर खतरा पैदा करेगी। इसके अतिरिक्त इस शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जबरन धन वसूली के लिए व्यवसायी वर्ग एचएनएलसी का प्रमुख लक्ष्य है। अंत में यह उल्लेख किया जाता है कि अपने अवैध उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एचएनएलसी ने अपने छिपने के विभिन्न अड्डों में भारी तादाद में अवैध शस्त्र और गोलाबारूद भी जमा कर रखे हैं।

डा. श्रीरंजन से पूछताछ करने के अतिरिक्त, मेघालय राज्य ने चार जिलों, अर्थात् पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, जैतिया हिल्स और रि-भोई, जहां एचएनएलसी को बहुत सक्रिय बताया जाता है, के उपायुक्तों तथा संबंधित पुलिस अधीक्षकों से भी पूछताछ की। पश्चिमी खासी हिल्स के उपायुक्त तथा पुलिस उपाधीक्षक, अर्थात् श्री मेबनशेलांग रिंजाह सिनरेम और श्री जी.डी. खरवनलांग क्रमशः एस डब्ल्यू 2 और एस डब्ल्यू 3 के रूप में कटघरे (विटनेस बॉक्स) में आए। मौखिक साक्ष्य देने के अतिरिक्त उन्होंने प्रदर्श एस डब्ल्यू 2/1 और प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/1 के रूप में साक्ष्य में अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए। इसी तरह, पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त श्री भालंग धर और पूर्व पुलिस अधीक्षक श्री ए. आर. मॉतहोह भी गवाहों के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने एस डब्ल्यू 4 और एस डब्ल्यू 5 के रूप में मौखिक साक्ष्य दिया और प्रदर्श एस डब्ल्यू 4/1 तथा प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/1 के रूप में साक्ष्य में अपने शपथपत्र भी प्रस्तुत किए। जैतिया हिल्स के उपायुक्त श्री संजय गोयल तथा पुलिस अधीक्षक श्री एम. के. सिंह एस डब्ल्यू 6 और एस डब्ल्यू 7 के रूप में उपस्थित हुए तथा उन्होंने क्रमशः एस डब्ल्यू 6/1 और एस डब्ल्यू 7/1 के रूप में दिए साक्ष्य में दिनांक 26 मार्च, 2009 के अपने-अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए। अंत में रि-भोई जिले के उपायुक्त तथा पुलिस उपाधीक्षक, अर्थात् सुश्री लवांडा डिंगडोह तथा श्री स्टीफन ए. रिंजाह क्रमशः एस डब्ल्यू 8 और एस डब्ल्यू 10 के रूप में कटघरे में आए तथा प्रदर्श एस डब्ल्यू 8/1 और प्रदर्श एस डब्ल्यू 10/1 के रूप में साक्ष्य में अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए।

अपने-अपने जिलों में एचएनएलसी की अवैध गतिविधियों के संबंध में उपर्युक्त सभी गवाहों ने कमोबेश एक जैसा साक्ष्य दिया। उनके मौखिक साक्ष्य तथा उनके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों का सार निम्न प्रकार है:-

- (1) कि एचएनएलसी का मुख्य उद्देश्य भारत संघ के भू-भाग से अलग होना है तथा इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए यह जबरन धन वसूली, अपहरण आदि जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त है।

- (2) कि एचएनएलसी के उल्फा, एनसीसीएन, एनडीएफबी और एनएलएफटी जैसे अनेक संगठनों के साथ संबंध हैं।
- (3) कि एचएनएलसी के शीर्ष नेता अभी भी बंगलादेश में छिपे हुए हैं तथा सीमा पार से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
- (4) एचएनएलसी के कौंडर, व्यवसायी वर्ग को मांग जारी करके निधियां जुटाने में लगे हुए हैं।
- (5) कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने तथा भारत की प्रभुसत्ता तथा भू-भागीय अखंडता को नष्ट और विघटित करने के उद्देश्य से एचएनएलसी के सदस्यों ने भी अपने पास भारी मात्रा में कथित अवैध शस्त्र और मोलाबारूद जमा कर रखे हैं।
- (6) कि एचएनएलसी के मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायी वर्ग है जिन्हें वे डराते-धमकाते हैं तथा उनसे जबरन धन वसूली करते हैं।
- (7) कि एचएनएलसी लोगों से गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग न लेने के लिए कहता रहा है। इस संगठन का मूल उद्देश्य एक स्वतंत्र राष्ट्र का दावा करना है। यह एक ऐसी मांग है जिससे भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता और बाहरी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
- (8) कि इस अधिनियम के कठोर उपबंधों का सहारा लेकर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से इस संगठन की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है।

बयानकर्ताओं ने अपने शपथपत्रों के साथ 16 नवम्बर, 2006 से अधिकरण के समक्ष शपथपत्र दायर करने की तारीख तक की अवधि के दौरान अपने-अपने जिलों में दर्ज प्राथमिकियों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। ये एफ आई आर मुख्यतः भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी/121/121ए/307/364/326/384/506/511/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए)/27(2)(3) के अंतर्गत दर्ज की गई हैं जो, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने अथवा युद्ध छेड़ने का प्रयास करने अथवा युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित हैं।

मैंने विभिन्न गवाहों द्वारा शपथपूर्वक दिए गए बयानों, भारत संघ तथा मेधालय सरकार की ओर से दायर किए गए शपथपत्रों तथा शपथपत्रों के साथ दायर किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है। दिए गए साक्ष्य तथा रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री का खंडन नहीं किया गया है तथा उन्हें चुनौती नहीं दी गई है। विभिन्न शपथपत्रों तथा शपथपूर्वक दिए गए बयानों से एचएनएलसी की राष्ट्र विरोधी तथा अलगाववादी प्रवृत्ति का पता चलता है। गवाहों ने यह भी बयान दिया है कि

एचएनएलसी ने ऐतिहासिक महत्व के अवसरों जैसे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर बंद का आह्वान किया था।

विभिन्न शपथपत्रों, रिकॉर्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से सिद्ध होता है कि एचएनएलसी का उद्देश्य अपनी स्वतंत्र पहचान और भारत के संविधान और प्रभुसत्ता से बाहर एक पृथक देश बनाना है। एचएनएलसी की सक्रियता के क्षेत्रों में प्रमुखतः पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, जैतिया हिल्स और रि-भोई जिले सम्मिलित हैं। इस संगठन के पास गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त किए हुए अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र हैं। यह संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो भारत की अखण्डता और संप्रभुता के लिए हानिकर हैं और यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से शस्त्र-कार्रवाई के जरिए हिंसक साधनों का सहारा ले रहा है। रिकॉर्ड में रखी गयी और सिद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि यह संगठन व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित नागरिकों से गैर-कानूनी ढंग से धन ऐंठने में लिप्त है और यह पुलिस कार्रमियों को निशाना बनाता रहा है जिनमें से कुछ, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, घायल हुए हैं और कुछ की मृत्यु हुई है। रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि एचएनएलसी के पूर्वोत्तर के पृथक्तावादी विद्रोही गुटों के साथ संबंध है और इसे उनका समर्थन प्राप्त है और यह संगठन पड़ोसी देश बंगलादेश में अपने शिविर स्थापित किए हुए है और यह गुप्त/प्रच्छन्न माध्यमों से बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और गोलाबारूद जुटा रहा है।

"विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" और "विधिविरुद्ध संगठन" की परिभाषा में क्या शामिल है जिसके तहत एचएनएलसी को प्रतिबंधित है, इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 2(ण) और 2(त) को देखना होगा जिसका पाठ निम्नानुसार है:-

"2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ण) "विधि विरुद्ध क्रिया" से किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में, ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा (चाहे कार्य करके, या तो बोले गए या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा) की गयी कोई ऐसी कार्यवाही अभिप्रेत है,

(i) जो किसी भी आधार पर चाहे कुछ भी हो, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्वर्पण या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाने को घटित करने, के लिए आशयित है या ऐसे दावे का समर्थन करती है या जो ऐसा अध्वर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यक्तियों के समूहों को उद्दिष्ट करती है या,

(ii) जिससे भारत की सम्प्रभुता या प्रादेशिक असंगतता का अनअंगीकरण होता है या उन पर आक्षेप होता है या जो

उन्हें विछिन्न कस्ती है या विछिन्न करने के लिए आशयित है, या

(iii) जो भारत के विरुद्ध अस्नेह कारित करता है या कारित करने के लिए अभिप्रेत है,

(त) "विधि विरुद्ध संगम" से कोई संगम अभिप्रेत है,-

(i) जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रिया है या जो व्यक्तियों को किसी विधि विरुद्ध क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसकी सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसी प्रक्रिया करने का उपक्रम करते हैं, या

(ii) जिसका उद्देश्य कोई क्रिया है, जो भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 153-क या 153-ख के अधीन दण्डनीय है या जो किसी ऐसे क्रिया को करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसी प्रक्रिया करने का उपक्रम करते हैं

परन्तु उपखण्ड (ii) में अन्तर्विष्ट कोई चीज जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगी।"

अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन का संदर्भ देना भी उपयुक्त होगा जो कि निम्नवत् हैं:-

#### "उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रवाद संबंधी समिति की सर्वसम्मत सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के अनुसरण में विधि के द्वारा संविधान (16 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा भारत की सम्प्रभुता और एकता के हित में निम्नलिखित के संबंध में उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई-

- i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ii) शान्तिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने का अधिकार; और
- iii) एसोशिएसन और यूनियन गठित करने का अधिकार।

2. इस विधेयक का उद्देश्य भारत की एकता और सम्प्रभुता के विरुद्ध चलाई जाने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां प्रदान करना है।”

एचएनएलसी के घोषित उद्देश्यों और इसके क्रियाकलापों के आलोक में, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसकी गतिविधियां और इसका संगठन उक्त अधिनियम की धारा 2(ण) और (त) के अर्थ के अंतर्गत विधिविरुद्ध है और तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि यदि एचएनएलसी को अपनी गतिविधियां जारी रखने दिया जाता है तो यह आगे भी विद्रोही और विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहेगा। मैं इस बात से भी संतुष्ट हूँ कि इस संगठन की गतिविधियों से भारत की सम्प्रभुता और भूभागीय अखण्डता विखण्डित हो सकती है और यदि इसे रोका नहीं गया या इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इससे न केवल इसके विधिविरुद्ध क्रियाकलाप बढ़ेंगे बल्कि राज्य में भारत से पृथक होने का वातावरण भी बन सकता है।

पूर्वोक्त कारणों से, मैं संतुष्ट हूँ कि एचएनएलसी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण थे तदनुसार, यह अधिकरण विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी केन्द्रीय सरकार की दिनांक 16 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि करता है।

दिनांक : 14 मई, 2009

रेखा शर्मा, न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी

[फा. सं. 11011/53/2008-एन. ई. III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2009

**S.O. 1372(E).**— In terms of section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Rekha Sharma, Judge Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) organization of Meghalaya as unlawful is published for general information:

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL  
CONSISTING OF HON'BLE MS. JUSTICE REKHA SHARMA

In the matter of: Notification No.S.O.2665(E) dated 16.11.2008, Government of India, Ministry of Home Affairs, Part II, Section (ii), declaring Hynniewtre National Liberation Council of Meghalaya as unlawful association.

ORDER

By notification No.S.O.2665(E) published on November 16, 2008 in the (Extraordinary) Gazette of India, the Central Government, Ministry of Home Affairs, in exercise of the powers conferred upon it under sub-section(1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the 'Act'), has declared Hynniewtre National Liberation Council of Meghalaya (hereinafter referred to "HNLC"), with all its factions, wings and front organization as an unlawful organization with immediate effect on the ground that the said organization and its various factions have as their professed aim and objective the secession of areas in the State of Meghalaya largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals from India through violent means.

It is stated in the notification that in order to achieve their objective, HNLC has been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization; maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern Region for carrying out acts of extortion and intimidation and maintaining camps in some neighbouring countries for the purpose of sanctuary and training of their cadres.



It is further stated in the notification that HNLC was involved in three incidents of violence each in 2006 and 2007 and one incident of violence in 2008 (upto June 30, 2008) resulting in killing of one and two persons including one security personnel in the years 2006 & 2007 respectively. It is also stated in the notification that the Central Government is of the opinion that, "the aforesaid activities of the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said HNLC would regroup and rearm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate its anti-national activities."

Since in terms of the Act, a reference has to be made to a Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there exists sufficient cause for declaring HNLC an unlawful association, the Government of India issued a notification dated December 11, 2008 under sub section (1) of Section 5 of the Act constituting this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring HNLC as unlawful association. The said notification reads as under:-

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS"  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 11<sup>th</sup> December, 2008

S.O.2860(E)- In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Ms. Justice Rekha Sharma, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as Unlawful Association.

[F.No.11011/53/2008-NE.-III]  
A.K.GOYAL, Jt.Secy."

Along with the aforesaid Gazette notification of December 11, 2008 a brief resume regarding the aims and objectives of HNLC was furnished for the perusal and information of this Tribunal which runs as follows:-

#### **"AIMS AND OBJECTIVES OF HNLC**

The HNLC was formed in 1992 with the aim of Liberation of Hynniewtrep People (Khasi and Jaintia tribals) from the authoritarian rule of the Indian Government, protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation, retain the indigenous culture and to eradicate social evils. It also vows to fight against any attempt to divide Khasi society.

#### **VIOLENCE PROFILE**

The violence by the outfit has declined significantly. During the years 2006, 2007 and 2008 (upto 30.06.2008), the HNLC was involved in three, three and one violent incidents respectively. These violent incidents by HNLC resulted in killing of one person and two persons (including one Security Force personnel) in the years 2006 and 2007 respectively. However, the outfit has regularly given calls every year for boycott of Republic Day and Independence Day celebrations and appeals to the people to observe bandh on these days as a mark of protest against the National Days. HNLC has also been opposing uranium mining in the State. On 10.01.2008, the outfit threatened that it would not spare any organization or individual supporting uranium mining in Meghalaya as the ore was the rightful property of the Hynniewtrep people (Khasi and Jaintia tribals) and not of India.

Interrogation of Julius Dorphang, self-styled Chairman of HNLC, who surrendered on 23.07.2007, has revealed that extortion from the Shillong region has been the main source of funds for the outfit.

#### **LINKS WITH UNDERGROUND OUTFITS OF NORTH EASTERN REGION**

The outfit continues to maintain links with the National Democratic Front of Boroland (NDFB), National Liberation Front of Tripura (Biswamohan Debbarma) and National Socialist Council of Nagaland (Isac-Muviah) [NSCN (I/M)]. According to available information, the outfit has camps or shelters in Bangladesh, and its top leaders, Bobby Marwein, Self-Styled Commander in Chief and Cheristerfield Thangkhiew, Self-Styled General Secretary, continue to operate from Bangladesh.

202541/09-3

**AREAS OF INFLUENCE, CADRE STRENGTH  
AND WEAPONRY OF THE OUTFIT**

The HNLC is primarily operating in Khasi Hills of Meghalaya. The cadre of HNLC is estimated at 50 or 60. The total weaponry of the outfit at present is estimated at 20 including AK series rifles, light Machine Guns and Rifles.

In the light of the aforesaid facts stated by the Central Government and the State Government, the HNLC was declared Unlawful Organization under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for a period of two years beyond 15.11.2008 on the following grounds:

- (i) Openly declared objective of HNLC for secession of areas in the State of Meghalaya largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals from India;
- (ii) Continued intimidation and extortion of civilian population by HNLC for collection of funds for their organization;
- (iii) Maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation;
- (iv) Maintenance of camps in Bangladesh for the purpose of sanctuary and training of their cadres."

Pursuant to the notification dated December 11, 2008 this Tribunal in its first sitting on January 09, 2009 directed issuance of notices under Section 4(2) of the Act to HNLC calling upon it to show cause within 30 days from the date of service of such notices as to why it should not be declared an unlawful association and why an order be not made confirming the declaration made in the notification dated November 16, 2008. Notices were also directed to be served on the aforesaid association by publication in the two National Daily newspapers, two local newspapers published in the locality where the association has its establishments or their presence is known in the State of Meghalaya and outside and also by affixing a copy thereof at conspicuous parts of the office, if any of the said association and by serving a copy of such notice wherever possible on the principal office

bearers, if any of the association at their addresses by registered post or otherwise. It was also directed that a proclamation be made by the beat of drums as well as by loudspeakers in the area about the contents of the notices and notification of the constitution of the Tribunal in the areas where the activities of the said association are ordinarily carried out. Furthermore, it was directed that the notices shall be pasted on the notice board of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil and office of the Deputy Commissioner and market places. Lastly, the Central Government was directed to ensure that publicity was given in the electronic media, i.e. by broadcasting/telecasting.

Consequent to the orders so passed, an affidavit dated February 25, 2009 was filed by Shri R. R. Jha, Director to the Government of India in the Ministry of Home Affairs affirming to the fact that the notices were served upon the said organization by different modes as directed in the order dated January 09, 2009. The Registrar to this Tribunal also filed his report dated February 25, 2009 verifying the steps taken by the Central Government/State Government in serving and publishing the notices by different modes. An affidavit dated February 21, 2009 was also filed by Dr. Shreeranjana, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department, Shillong. The said Dr. Shreeranjana too affirmed to the fact that notices as directed by the Tribunal in its order dated January 09, 2009 were issued in the manner indicated therein. He also placed on record copies of the newspaper clippings carrying the notices; proof of the fact that notices were broadcasted through Shillong Station of All India Radio and were telecast through Doordarshan Kendra, Shillong.

In spite of service of notices, nobody came forward to represent the HNLC nor any petition, message, reply or letter have been received from the said organization by the Tribunal or its Registrar. Hence, the matter was fixed for recording ex-parte evidence and the same was recorded on March 26, 2009 and March 27, 2009 at Shillong and then again on April 20, 2009 at Delhi.

The Central Government in support of its case examined Shri R R Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs. He had also filed an affidavit dated February 26, 2009 which he tendered in evidence. The same was exhibited as SW-9/1. He deposed that the facts relating to the activities of HNLC are contained in his affidavit and that the same be read as part of his evidence. As per the affidavit of Shri R R Jha, HNLC was formed in 1992. Its aims and objects include liberation of Hynniewtrep people (Khasi and Jaintia tribals) from the alleged authoritarian rule of the Indian Government. The objective of the outfit is to secede areas in the State of Meghalaya largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals from India. It is further stated in the affidavit that HNLC vows to fight against any attempt to divide khasi society and it regularly gives calls every year for boycott of Republic Day and Independence Day celebrations and appeals to the people to observe bandh on these days as a mark of protest against national holidays. It is also stated in the affidavit that to achieve its objectives, HNLC has continued to intimidate and engage in extortion from civilian population for collection of funds for their organization and this fact was also revealed from the interrogation of Julius Dorphang, self-styled Chairman of HNLC who surrendered on July 23, 2007 and disclosed that extortion from the Shillong region has been the main

source of funds for the outfit. It is also stated in the affidavit that HNLC has opposed uranium mining in the State and that on January 10, 2008, the outfit threatened that it would not spare any organization or individual supporting uranium mining in the Meghalaya as the ore was the rightful property of the Hynniewtrep people (Khasi and Jaintia tribals) and not of India. As per the affidavit, the outfit continues to maintain links with the National Democratic Front of Boroland (NDFB), a banned organization; National Liberation Front of Tripura (Biswamohan Debbarma) again a banned organization and National Socialist Council of Nagaland (Isak-Muviah), {NSCN (I/M)}. It has camps or shelters in Bangladesh and its top leaders, Bobby Marwein, self-styled Commander-in-Chief and Cheristerfield Thangkhiew, self styled General Secretary continue to operate from Bangladesh. The organization is said to be maintaining links with unlawful associations in order to achieve its objective. The deponent Shri R.R.Jha along with his affidavit also placed on record details of the incidents of violence by HNLC during the year 2006, 2007 and 2008 and proved the same as Ex.SW-9/2. As per Ex.SW-9/2, on October 30, 2007, police intercepted a vehicle at Cleave Colony in which three HNLC UGs were travelling and that led to an encounter, in which three UGs and two sympathizers were killed and two police personnel were also injured (Police Station Laitumkhrah-Shillong, East Khasi Hills District). Again on November 07, 2007, an encounter took place between police and HNLC UGs at Pahamumdoh resulting in killing of a UG and severe injuries to Deputy Superintendent of Police (R.P.Diengdoh). In the same incident, two UGs were apprehended and remaining two managed to escape. Later, the injured Deputy Superintendent of Police succumbed to the

injuries in the hospital (Police Station Nongpoh, Ri-Bhoi District). Yet, again on December 16, 2007, police apprehended two HNLC UGs from Narpuh reserved forest. On the basis of leads provided by them, police raided their hideout, in the jungle which led to an encounter with UG (HNLC-4, NLFT/B-3). However, no casualty/injury was reported from either side and UGs managed to escape (police station - Khelrihat Jaintia Hills District). Lastly, on March 26, 2008, on the information from I.B., Meghalaya, police busted a module of HNLC. In the encounter, two UGs were killed and six were arrested (Police Station Umkung, Jaintia Hills District).

As regards the incident of extortion, it is revealed from Ex.SW-9/2 that on February 15, 2008, HNLC had served a demand note of Rs.1 crore to M/s. Hills Cement Factory, Mynkre (Jaintia Hills District) and threatened dire consequences in case of failure to make payment. Again on May 20, 2008, Meghalaya police apprehended one HNLC cadre (B-Nonglait-23 years) while he along with two cadres was trying to extort money from coal exporters at Nongjiri Village (West Khasi Hills District). The other two however managed to escape.

Insofar as the State of Meghalaya is concerned, it had examined its Commissioner and Secretary, Political Department, Government of Meghalaya, namely, Dr. Shreeranjana who also tendered in evidence his affidavit dated February 21, 2009 and proved the same as Ex.SW1/1. He deposed that HNLC is very active in four Districts of Meghalaya, namely, East Khasi Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills and Ri-bhoi District. He further deposed that the aim and objectives of HNLC have been stated in detail in his affidavit. As per him, the HNLC is trying to achieve its aim and objectives by way of armed struggle and is



collaborating with NSCN, NDFB and NLFT. He further deposed that the ban earlier imposed on HNLC has been helpful in curbing their activities and bringing its members to book and prayed that the ban imposed be continued in view of the fact that they are still indulging in the same type of illegal activities. According to his affidavit Ex.SW1/1 which, as noticed above, he tendered in evidence, HNLC is indulging in extortion and looting of civilian population, businessmen etc. for collection of funds. It also hires services of women to extort money from several houses and business establishments. In support, newspaper cuttings carrying the news to the said effect have been placed on record as Ex.SW1/9. The affidavit goes on to say that HNLC is maintaining links with almost all the militant groups in the North-East to procure arms and carry out extortion drive and is banking on the help by militant outfits, like NLFT in Jaintia Hills, NSCN (I-M) in West Khasi Hills and NDFB in Ri-bhoi District. Here again newspaper cutting carrying such information has been placed and proved on record as Ex.SW1/10. It is also stated in the affidavit that top cadres of HNLC are hiding in Bangladesh from where they operate their unlawful, nefarious and anti-national activities. It is further stated that HNLC planned to kidnap industrialists from Brynihat for ransom and has been camping in Paham Umdoh forest of Ri-bhoi District. However, the plan was foiled as the police team led by Deputy Superintendent of Police, Raymond Diengdoh raided the hideout of the outfit. In the encounter that followed, the Deputy Superintendent of Police was critically injured and he succumbed to his injuries on way to the Army Hospital. One militant was also killed and two militants were arrested from the encounter site. This incident finds mention in a newspaper cutting Ex.SW1/11. It is also

stated in the affidavit that HNLC has established strong relationship with other anti-national insurgent groups of the States of North-Eastern India, like the United Liberation Front of Assam (ULFA), the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the National Liberation Front of Tripura (NLFT) which leads to a very strong belief that the HNLC will create more trouble in the near future and shall pose serious threat to national security and sovereignty of India. Yet, further it is stated in the affidavit that the business community is the main target of HNLC for extorting money. Lastly, it is stated that the HNLC is also carrying and keeping with them illegal arms and ammunitions in sizeable quantity in various hideouts with a view of achieve their unlawful aims and objectives.

Besides examining Dr. Shreeraanjan, the State of Meghalaya also examined the Deputy Commissioners of four Districts, namely, East Khasi Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills and Ri-bhoi District where HNLC is stated to be very active and operating as also their respective Superintendents of Police. The Deputy Commissioner of West Khasi Hills and the Deputy Superintendent of Police, namely, Shri Mebanshailang Rynjah Synrem and Shri G.D.Kharwanlang entered the witness-box as SW.2 & SW.3 respectively. Besides giving oral evidence, they also tendered their affidavits in evidence as Ex.SW2/1 & Ex.SW3/1. Likewise, the Deputy Commissioner of East Khasi Hills Shri Bhalang Dhar and the erstwhile Superintendent of Police Shri A.R.Mawthoh also appeared as witnesses. They gave oral evidence as SW4 and SW5 and also tendered their affidavits in evidence as Ex.SW4/1 & Ex.SW5/1. The Deputy Commissioner of Jaintia Hills Shri Sanjay Goyal and Superintendent of Police, Jaintia Hills, Shri M.K.Singh appeared as SW6

& SW7 and tendered their respective affidavits dated March 26, 2009 in evidence as Ex.SW6/1 and SW7/1 respectively. Lastly, the Deputy Commissioner of Ri-Bhoi District and the Deputy Superintendent of Police, namely, Ms. Lawanda Diengdoh and Shri Stephen A.Rynjah entered the witness-box as SW.8 & SW.10 respectively and also tendered in evidence their affidavits as Ex.SW8/1 & Ex.SW10/1.

All the above witnesses more or less deposed on similar lines as regards the unlawful activities of HNLC vis-à-vis their respective Districts. The sum and substance of their oral evidence and affidavits filed by them is to the following effect:-

- (1) that the main objective of HNLC is to secede from the territory of Union of India and in order to achieve this object, it is indulging in unlawful activities such as extortion, kidnapping, etc.
- (2) the HNLC has links with other unlawful organization, like ULFA, NSCN, NDFB & NLFT.
- (3) that the top ranking leaders of HNLC are still hiding in Bangladesh and are carrying out their activities from across the border.
- (4) the cadres of HNLC are engaged in raising funds by issuing demand to the business community.
- (5) that the members of HNLC are still carrying on and are reportedly keeping with them illegal arms and ammunitions in sizeable quantity, with a view to carry out their aims and objectives and to subvert and disrupt the sovereignty and territorial integrity of India.

2025 4 Nov - A

- (6) that the main targets of the HNLC are government officials and business community whom they intimidate and extort money from them.
- (7) that HNLC have been asking people not to participate in the celebrations of the Republic Day and the Independence Day. The basic object of this organization is to claim an independent State which demand poses a serious threat to the sovereignty, integrity and internal and external security of India.
- (8) that the ban imposed by the Central Government has helped in curbing the unlawful activities of the organization by taking recourse to stringent provisions of the Act.

The deponents have filed along with their affidavits copies of the FIRs registered in their respective Districts during the period November 16, 2006 till the date of filing of affidavits before the Tribunal. These FIRs have been mainly registered under Sections 120B/121/121A/307/364/326/384/ 506/511/34 of the Indian Penal Code and Section 25(1-A)/27(2)(3) of the Arms Act which inter-alia relate to waging or attempting to wage war or abetting waging of war, against the Government of India.

I have perused the statements made on oath by the various witnesses, the affidavits filed on behalf of the Union of India and the Government of Meghalaya and the documents filed along with the affidavits. The evidence led and the material placed on record has gone unrebutted and unchallenged. The various affidavits and the statements made on oath reveal anti-national and secessionist

tendency of HNLC. It is also deposed by the witnesses that HNLC had given calls for bandhs on days of historical importance, like Republic Day and Independence Day.

It stands established from the various affidavits and documents placed on record as well as from the statements of the witnesses that the objective of HNLC is to establish independent identity and a separate country outside the Constitution and sovereign boundaries of India. The area of operation of HNLC mainly includes East Khasi Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills and Ri-bhoi Districts. The organization possesses sophisticated fire arms procured through illegal means. It is indulging in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India and is resorting to violent means through arms actions with a view to achieve its objective. The FIRs placed and proved on record indicate that the outfit is indulging in extortion and illegal collection of money from civilian including businessmen, traders and has been targeting police personnel some of whom, as noticed above, sustained injuries and some succumbed to their injuries. It also transpires from the material on record that HNLC has links and support of other North-Eastern secessionist insurgent groups and it is continuing to maintain its camps in neighbouring Bangladesh and is procuring large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels.

What constitutes an "unlawful activity" and "unlawful association" under which HNLC has been so declared is defined in Sections 2(o) and 2(p) of the Act. The same are as under:-

2. Definitions. – In this Act, unless the context otherwise requires –

XXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX

(o) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise)

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or

(iii) which causes or is intended to cause disaffection against India.

(p) "unlawful association" means any association –

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under Section 153A or Section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity;

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir."

It will also be appropriate to refer to the Statement of Objects and Reasons of the Act which are as under:-

#### **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Pursuant to the acceptance by Government of a unanimous recommendation of the Committee on National Integration and Regionalism appointed by the National Integration Council, the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, was enacted empowering Parliament to impose, by law,

reasonable restrictions in the interests of the sovereignty and integrity of India, on the -

- (i) freedom of speech and expression.
- (ii) right to assemble peaceably and without arms; and
- (iii) right to form associations or unions

2. The object of this Bill is to make powers available for dealing with activities directed against the integrity and sovereignty of India."

In view of the professed aims and objectives of the HNLC and its activities, as noticed above, there is no manner of doubt that its activities and its association are unlawful within the meaning of Section 2(o) & (p) of the Act and accordingly, I am satisfied that if HNLC is allowed to continue with its activities, it would further indulge in insurgent and unlawful activities. I am further satisfied that its activities would lead to disruption of the sovereignty and territorial integrity of India and if it is not banned or checked, not only the unlawful activities would increase but also an atmosphere may be created in the State for secession from India.

For the foregoing reasons, I am satisfied that there was sufficient cause for declaring HNLC an unlawful association. This Tribunal, accordingly, confirms the declaration made by the Central Government vide notification dated November 16, 2008 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

Dated : May 14, 2009

REKHA SHARMA, Judge, Presiding Officer

[F. No. 11011/53/2008-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.